

प्रेषक,

डी0एस0 गब्याल,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
शहरी विकास निदेशालय,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 02 अगस्त, 2016

विषय: "अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)" के अन्तर्गत चयनित 06 नगर निगमों हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या: K-14012/158/2015-SC-II, दिनांक 20.01.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अमृत योजनान्तर्गत चयनित 06 नगर निगमों हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 की कार्ययोजना के सापेक्ष कुल ₹133.68 करोड़ केन्द्रांश अनुमोदित करते हुए उक्त के सापेक्ष 20 प्रतिशत ₹26.74 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अमृत योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि ₹26.74 करोड़, एवं उक्त के सापेक्ष देय राज्यांश ₹2.97 करोड़, इस प्रकार कुल ₹29.71 करोड़ (रुपये उन्तीस करोड़ इकहत्तर लाख मात्र) की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त धनराशि कुल ₹29.71 करोड़ (रुपये उन्तीस करोड़ इकहत्तर लाख मात्र) आपके द्वारा आहरित कर योजनान्तर्गत चयनित नगर निगमों को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।
- स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा एवं मितव्ययिता की मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।
- योजनाओं की स्वीकृति के समय योजनाओं को पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि को दृष्टिगत रखते हुए Project Implementation Schedule (CPM/CPERT/BAR CHART) तैयार किया जाना चाहिए, जिससे Cost Overrun and time over run से बचा जा सके।
- स्वीकृत परियोजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी guidelines/Toolkit एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों के अनुसार निविदाएं टू-बिड सिस्टम पर तकनीकी एवं वित्तीय बिड के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुए किया जाय, ताकि

- (viii) सक्षम व अनुभवी फर्मों/निविदादाताओं द्वारा ही निविदा प्रक्रिया में भाग लिया जाय तथा उच्च स्तरीय फर्म का चयन किया जा सके।
- (ix) एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
- (x) निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
- (xi) परियोजनान्तर्गत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।
- (xii) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी, जिसमें कि भौतिक प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होगा।
- (xiii) मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
- (xiv) स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।
- (xv) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- (xvi) कार्य पूर्ण होने पर इस वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र यथासमय शासन को प्रस्तुत किए जायेंगे। योजना के लिए स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण भी शासन को प्रेषित किया जायेगा।
- (xvii) निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।
- (xviii) धनराशि का दिनांक 31-3-2016 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

2- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-13-लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना-11-अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा०सं०- 04/XXVII(2)/2016, दिनांक 27.04.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न-एलॉटमेंट आई०डी० S..16.05.13.0010

भवदीय,  
/  
(डी०एस० गब्याल)  
सचिव।

संख्या- 634-(1)/IV(2)-श०वि०-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।

2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/ऊधमसिंह नगर/नैनीताल।
6. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रूद्रपुर/रूड़की/हल्द्वानी-काठगोदाम।
7. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

*21.1.11*  
( डा0 वी0षणमुग्गम )  
अपर सचिव।

